IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2320-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 10, Issue 1, January 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.512

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com |

|| Volume 10, Issue 1, January 2021 ||

DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1001094

क्वाड: हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशो के हितो का रक्षक: कल्पना या वास्तविकता

Pradeep Kumar Sharma

Assistant Professor, Political Science, Government College, Baseri, Dholpur, India

सार

काफ़ी चर्चा के बावजूद टोक्यो में क्वॉड मंत्री-स्तरीय बैठक अनुमानों के मुताबिक और आम बैठक जैसी ही रही. जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मेज़बानी में यह बैठक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर हुई पहली "स्टैंड-अलोन" (स्वतंत्र रूप से) बैठक के बाद पहली बैठक थी. सबसे ज़्यादा ध्यान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने खींचा, जिन्होंने "हमारे लोगों और साझीदारों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना के शोषण, भ्रष्टाचार और ज़बरदस्ती से बचाने के लिए" लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग की अपील की.यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र बाकी दुनिया के साथ, कोविड-19 वैश्विक महामारी के असर से उबर रहा है. इसके साथ ही चीन की आक्रामकता ताइवान जलसंधि, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी लद्दाख और हां हांगकांग में भी दिख रही है. हालांकि, यह उम्मीद कि बैठक में क्वॉड के "संस्थानीकरण" की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं, खोखली साबित हुई. जैसी कि उम्मीद की जा रही थी सबसे ज़्यादा ध्यान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने खींचा, जिन्होंने "हमारे लोगों और साझीदारों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना के शोषण, भ्रष्टाचार और ज़बरदस्ती से बचाने के लिए" लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग की अपील की. इस संदर्भ में, उन्होंने पूर्वी चीन सागर, मीकॉन्ग, हिमालय और ताइवान जलसंधि में चीनी गतिविधियों की चर्चा की.

परिचय

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (जिसे क्वाड (Quad) के नाम से भी जाना जाता है) संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, जो कि सदस्य देशों के बीच अर्ध-नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना विनिमय और सैन्य प्रशिक्षण द्वारा बनाए रखा जाता है। इस मंच की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे (Shinzō Abe) ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी (Dick Cheney), ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड (John Howard) और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी। जापान और भारत के चीन के साथ कथित गठबंधन में शामिल होने से, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड द्वारा चिंताओं को दर्शाते हुए 2007 में संबंध-विच्छेद कर क्वाड का पहला संगठन समाप्त कर दिया था। हॉवर्ड के उत्तराधिकारी केविन रुड ने इस पद की फिर से पुष्टि की। रुड और उनके उत्तराधिकारी जूलिया गिलार्ड ने, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाया। भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका मालाबार के माध्यम से आज भी संयुक्त नौसैनिक प्रशिक्षण जारी रखते हैं। [1] हालांकि, 2017 एशियन (ASEAN) शिखर सम्मेलन के दौरान, सभी चार पूर्व सदस्यों ने चतुर्भुज गठबंधन को पुनः स्थापित करने के लिए बातचीत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल (Malcolm Turnbull) के साथ, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन और इसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के कारण दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच सुरक्षा समझौते को पुनः स्थापित करने के लिए मनीला में सहमत हुए थे। क्वाड राष्ट्र और चीन

बैठक में मौजूद अन्य मंत्री अधिक संयमित थे और सीधे चीन का नाम लेने से बचे. इसके बावजूद कि भारत अपनी सीमाओं पर चीन के साथ समस्याओं का सामना कर रहा है भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने संबोधन में, "समान सोच वाले देशों द्वारा समन्वित प्रतिक्रिया" पर ज़ोर दिया. उन्होंने आगे कहा, "हम नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क़ानून के शासन, पारदर्शिता, अंतरराष्ट्रीय समुद्र में आवागमन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं." यह एक मानक फ़ॉर्मूला था, लेकिन "क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान" के संदर्भ का आशय साफ था, हालांकि, उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों में चीन का कोई ज़िक्र नहीं था. मंत्री इस बात पर भी स्पष्ट थे कि भारत का उद्देश्य, "इस क्षेत्र में वैध और महत्वपूर्ण हित रखने वाले सभी देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना है."

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com |

|| Volume 10, Issue 1, January 2021 ||

DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1001094

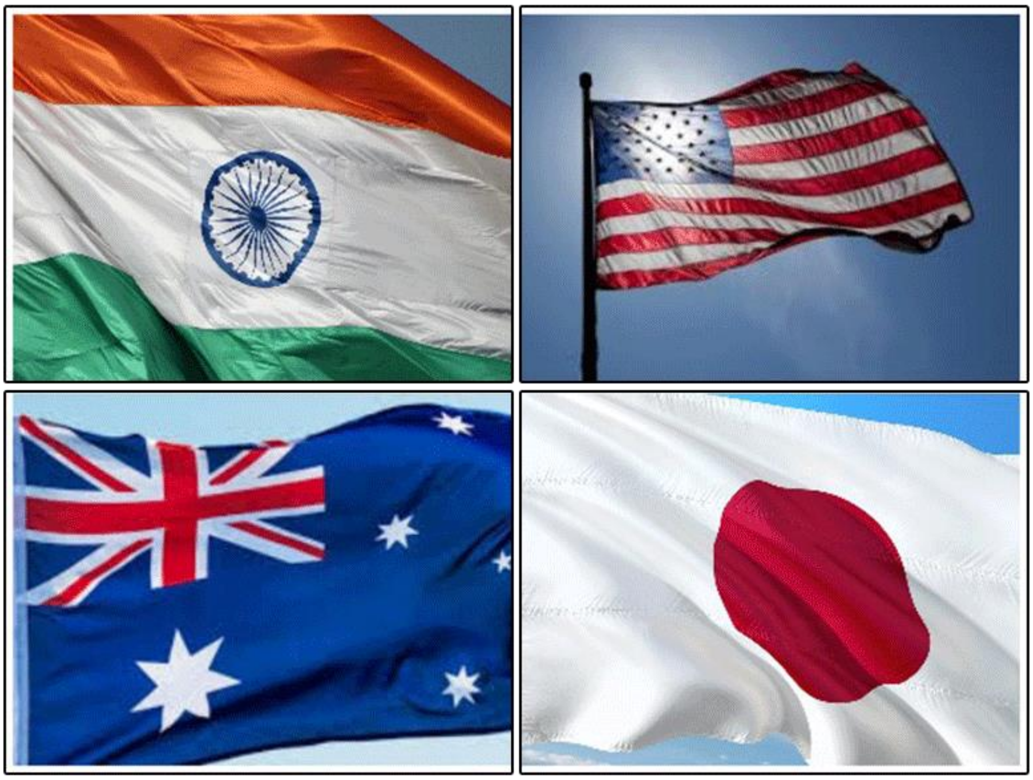

यह साफ होना चाहिए कि हालांकि, जून 2018 में शांगरी-ला वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्देशित भारत की एक हिंद-प्रशांत नीति है, यह उस समूह का हिस्सा नहीं है जो "हिंद-प्रशांत" क्षेत्र को "निर्बाध और खुला" रखने का हिमायती है. हालांकि, यह मिथ्या आशा है कि नई दिल्ली आगामी गर्मियों में भारी गतिरोध के बावजूद जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह क्वॉड का सक्रिय हिमायती बन जाएगा.[2]

क्वॉड का लोकतांत्रिक देशों के साझा हितों के आधारित पर एक सकारात्मक एजेंडा है. इन हितों में व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन, अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत विवादों को निपटाने का महत्व शामिल है. हालांकि, मौजूदा समय में ध्यान कोविड-19 से उबरने पर था. ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने ने भी चीन का नाम लेने से परहेज किया क्योंकि उनका इस बात पर ज़ोर था कि क्वॉड का लोकतांत्रिक देशों के साझा हितों के आधारित पर एक सकारात्मक एजेंडा है. इन हितों में व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन, अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत विवादों को निपटाने का महत्व शामिल है. हालांकि, मौजूदा समय में ध्यान कोविड-19 से उबरने पर था. उन्होंने समुद्री सुरक्षा, साइबर मामलों, टेक्नोलॉजी, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहित क्षेत्रों में लंबी दूरी के सहयोग की बात की और चीन पर निशाना साधते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर स्थानांतरित करने और "गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे" को विकसित करने के लिए बीजिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चल रहे प्रयासों का ख़ासतौर से ज़िक्र किया.

बैठक और मंत्री-स्तरीय डिनर के बाद जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रियों ने "उत्तर कोरिया, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया." इसमें चीन या पूर्वी लद्दाख गतिरोध का कोई ज़िक्र नहीं था. प्रेस विज्ञप्ति में ज़्यादा देशों, ख़ासकर आसियान के साथ सहयोग को व्यापक बनाने की बात कही गई थी.

एक मायने में, जो बात सबको पता है मगर कोई बोलना नहीं चाहता वह है आसियान. दक्षिण चीन सागर और मीकॉन्ग जैसे बहुत से मुद्दे जिन पर क्वॉड बात कर रहा है, आसियान से संबंधित हैं. हालांकि, अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि आसियान उन पर एकजुट रुख़ अपनाने को तैयार है. क्वॉड के लिए आसियान देशों के सहयोग के बिना इनको प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल होगा. मारिस पायने ने आसियान की केंद्रीय स्थिति को लेकर अपनी टिप्पणी और हिंद-प्रशांत एजेंडे की क़ामयाबी के लिए आसियान के नेतृत्व वाली व्यवस्था की ज़रूरत की बात कही. इसी तरह, जापानी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रियों ने "आसियान की एकता और केंद्रीय स्थिति के लिए अपने मज़बूत समर्थन को दोहराया." लेकिन ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फ़ोरम (ARF) और आसियान डिफ़ेंस मिनिस्टर्स मीटिंग (ADMM) प्लस, जिसका चीन भी एक सदस्य है, जैसे सुरक्षा तंत्र को क्वॉड द्वारा धीरे-धीरे और मज़बूती से किनारे लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अलग एजेंडे पर काम कर रहा है .[3]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com |

|| Volume 10, Issue 1, January 2021 ||

DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1001094

दक्षिण चीन सागर और मीकॉन्ग जैसे बहुत से मुद्दे जिन पर क्वॉड बात कर रहा है, आसियान से संबंधित हैं. हालांकि, अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि आसियान उन पर एकजुट रुख़ अपनाने को तैयार है. क्वॉड के लिए आसियान देशों के सहयोग के बिना इनको प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल होगा. हिंद-प्रशांत पर जून 2019 की आसियान आकलन रिपोर्ट ने जानबूझकर किसी भी नए तंत्र को बनाने या मौजूदा की जगह दूसरा तंत्र बनाने से ख़ुद को अलग रखा. किसी भी हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए आसियान की केंद्रीय स्थिति को रेखांकित करने के उद्देश्य से, इसने आसियान के नेतृत्व वाले ARF, ADMM प्लस और ऐसे ही अन्य संगठनों के तंत्र को ज़्यादा मजबूत करना और इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना लक्ष्य घोषित किया है. लेकिन जैसा कि प्रो. स्वर्ण सिंह ने लिखा है, क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के मुद्दे पर आसियान की नेतृत्वकारी भूमिका को लेकर स्पष्ट मतभेद रहा है. वह बताते हैं कि "आसियान की केंद्रीय स्थिति इस आश्वासन पर टिकी थी कि, प्रमुख शक्तियों के बुनियादी हितों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा" लेकिन अब "चीन को इस व्यवस्था की मदद से वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का मौका देकर आश्वासन को तोड़ा जा रहा है."

आश्चर्य नहीं कि इसकी विदेश नीति की सक्रियता को देखते हुए, बीजिंग अब पहले की तुलना में हाल के दिनों में क्वॉड का ज़्यादा आलोचक हो गया है. पिछले महीने, चीन के उप विदेश मंत्री और भारत में पूर्व राजदूत लुओ ज़ाओहुई ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ सी (UNCLOS) को लेकर उलटा दूसरों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और कहा कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में क़ानून का पालन किया है. उन्होंने अमेरिका पर क्वॉड को बनाने "चीन विरोधी मोर्चा, जिसे मिनी-नाटो भी कहा जाता है" का आरोप लगाया.

विचार-विमर्श

भारत हाल के वर्षों में, चीन द्वारा अंतरराष्ट्रीय मापदंडों का उल्लंघन, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में पुनर्निर्मित द्वीपों पर सैन्य सुविधाओं का निर्माण, और इसकी बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति, भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती पेश करती है। चीन की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत चीन पर रणनीतिक स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्ध होकर, एक ओर चीन और दूसरी ओर अमेरिका को संतुलित कर रहा है, जो आमतौर पर चीन को आश्वस्त कर रहा है। भारत ने अमेरिका और जापान के बीच मालाबार त्रिपक्षीय समुद्री प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी अनुमति नहीं दी थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल ही में ममल्लापुरम शिखर सम्मेलन एक सकारात्मक विकास है, जो दोनों पक्षों के हितधारकों को रणनीतिक मार्गदर्शन देने के लिए महत्वपूर्ण है।

पिछले एक दशक में, जापान ने चीन के क्षेत्रीय संक्रमण से संबंधित चिंताओं को व्यक्त किया है। चीन के साथ व्यापार की मात्रा जापानी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनी हुई है, जहां 2017 की शुरुआत के बाद से जापान के आर्थिक विकास में शुद्ध निर्यात का एक तिहाई योगदान रहा था। इसलिए, इसके महत्व को देखते हुए, जापान चीन के साथ अपनी आर्थिक जरूरतों और क्षेत्रीय चिंताओं को संतुलित कर रहा है। जापान ने तीसरे देश में बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों में भाग लेकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) में शामिल होने पर भी सहमति व्यक्त की है। इस तरह, जापान चीन के साथ संबंधों में सुधार करते हुए उन देशों में चीनी प्रभाव को कम कर सकता है।[4]

क्वॉड का ध्यान मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर पर है. हालांकि, भारत और अब फ्रांस व जर्मनी जैसे देशों को एक व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति की ज़रूरत है, जो पूरे हिंद महासागर के साथ-साथ प्रशांत को भी ध्यान में रखे.

क्वॉड का ध्यान मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर पर है. हालांकि, भारत और अब फ्रांस व जर्मनी जैसे देशों को एक व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति की ज़रूरत है, जो पूरे हिंद महासागर के साथ-साथ प्रशांत को भी ध्यान में रखे. शांगरी-ला डायलॉग के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की दृष्टि में, हिंद-प्रशांत क्षेत्र "अफ़्रीका के तट से अमेरिका तक" फैला है, जहां भारत "लोकतांत्रिक और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देगा, जिसमें सभी राष्ट्र- छोटे और बड़े फल-फूल सकें."

फ़्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने हाल के दिनों में एक हिंद-प्रशांत रणनीति की ज़रूरत की बात करना शुरू कर दिया है, जिसका दायरा सुरक्षा के मुद्दों से आगे है. इस दृष्टिकोण से हिंद-प्रशांत के बारे में एक निश्चित दुविधा है. यह आर्थिक अवसर का क्षेत्र है, साथ ही समस्याओं की भी भरमार है. लोकतांत्रिक देशों की साझेदारी का लक्ष्य अवसरों को बढ़ाने और समस्याओं से असरदार ढंग से निपटना है. भारत की पश्चिमी प्रशांत और पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी है. लेकिन पश्चिमी हिंद महासागर में इसके ज़्यादा व्यापक और जटिल हित हैं, जहां यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने का बड़ा मौका है. भारत की पश्चिमी प्रशांत और पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी है. लेकिन पश्चिमी हिंद महासागर में इसके ज़्यादा व्यापक और जटिल हित हैं, जहां यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने का बड़ा मौका है.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com |

|| Volume 10, Issue 1, January 2021 ||

DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1001094

हिंद-महासागर में सहयोग का दायरा सुरक्षा, पारिस्थितिकी, व्यापार, आपदा राहत, विकास और ऐसे तमाम मामलों में है. अंतरराष्ट्रीय क़ानून के नियम, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, जलवायु परिवर्तन से निपटने या व्यापार और औद्योगिक नीतियों के पालन के लिए समान विचारधारा वाले देशों से गठबंधन करने की ज़रूरत है. लेकिन पॉलिसी के दायरे में हिंद-प्रशांत के सिर्फ एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को शामिल करने की ज़रूरत है.

परिणाम

ऑस्ट्रेलिया अपनी भूमि, बुनियादी ढांचे और राजनीति में चीन की बढ़ती रुचि और अपने विश्वविद्यालयों पर प्रभाव के बारे में चिंतित है। समृद्धि के लिए चीन पर अपनी अत्यधिक आर्थिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति का पालन किया था। इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका गठबंधन को भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को फिर से हासिल करने के अवसर के रूप में देखता है। अमेरिका ने रूस के साथ चीन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और भारत-प्रशांत रणनीति पर अमेरिकी रक्षा-मंत्रालय की रिपोर्ट में रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में वर्णित किया है।
वहीं ये समूह 10 वर्ष की निष्क्रियता के बाद हाल ही में 2018 में सक्रिय हुए थे। लेकिन क्वाड का प्रारब्ध अभी भी काफी दुर्बल है। जैसा की ऊपर बताया गया है कि क्वाड का पहला प्रयास तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड द्वारा संबंध-विच्छेद कर लिए गए थे। आज, हालांकि, चीनी प्रतिष्ठा तीव्र चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सभी क्वाड में सक्रिय हैं, लेकिन भारत निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि भारत वुहान शिखर सम्मेलन के बाद क्वाड के बारे में कम उत्साही था।[5]
अप्रैल में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के वुहान में आमंत्रित किया था। शी जिनपिंग का फैसला असाधारण रूप से कूटनीति साबित हुआ। 2017 में द्विपक्षीय संबंध एक निम्नतम स्तर तक पहुंच गए थे, जो मुख्य रूप से डोकलाम में महीनों के सैन्य गतिरोध से उपजा था, जिसने संभवत: पहले स्थान पर क्वाड को फिर से शामिल करने के भारत के फैसले को तीव्र कर दिया था। क्वाड में भारत की भागीदारी के लिए परेशानी का दूसरा संकेत जून में सिंगापुर में वार्षिक शांगरी-ला संवाद में आया। मोदी द्वारा मुख्य भाषण में क्वाड के उद्देश्यों का मिलान करते हुए, एक शांतिपूर्ण और स्थिर इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की बात की, तब भी उन्होंने क्वाड को आमंत्रित करने के अवसर को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय कहा कि "भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को रणनीति के रूप में या सीमित सदस्यों के क्लब के रूप में नहीं देखता है।"

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख लोकतंत्रों का रणनीतिक गठबंधन क्वाड अब संकल्पना से अधिक यथार्थ का रूप ले रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक वक्त इसका उपहास उड़ाते हुए इसे सुर्खियां बटोरने की कवायद बताया था, जो प्रशांत या हिंदू महासागर में किसी बुलबुले के मानिंद कहीं गुम हो जाएगी। हालांकि, चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते ही आस्ट्रेलिया-भारत-जापान और अमेरिका का क्वाड गठबंधन जोर पकड़ रहा है। चूंकि अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर पड़ रहा है तो अमेरिका को अपने साथियों संग मिलकर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। एक खुले एवं स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड अमेरिकी रणनीति के केंद्र में है। आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ 'आकस' जैसी पहल के बावजूद अमेरिका के लिए क्वाड की अहमियत जरा भी कम नहीं। स्पष्ट है कि भारत, जापान और आस्ट्रेलिया को साथ लिए बिना अमेरिका एशिया में स्थायित्वपूर्ण शक्ति संतुलन नहीं बना सकता। अमेरिका भी इसे भलीभांति समझता है। यही कारण है जहां लंबे समय तक क्वाड की कोई बैठक नहीं हुई, वहीं जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद 14 महीनों के भीतर क्वाड नेताओं की चार बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, फिर भी इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि क्वाड की राह में अभी भी तमाम चुनौतियां कायम हैं। सदस्य देशों को उनका समाधान तलाश इस संगठन को तार्किक बनाने के लिए सक्रिय रहना होगा। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका और भारत इस समय चीन के भीमकाय व्यापार अधिशेष में सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। इसी आर्थिक ताकत के दम पर चीन का सामरिक खतरा बढ़ रहा है। क्वाड का एक उद्देश्य चीन की सामरिक शक्ति से उपजे खतरे की काट करना है। दूसरी ओर आस्ट्रेलिया एवं जापान, दोनों ने बीजिंग प्रवर्तित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी 'आरसेप' को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें 'आरसेप' से भारी आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है, भले ही इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार के गणित को तय करने में चीन की ताकत ही क्यों न बढ़ जाए। चीन लंबे समय से विदेशी व्यापार को राजनीतिक संबंधों से अलग रखने की मुहिम चला रहा है और यह रणनीति क्वाड सदस्य देशों के साथ बढ़िया साबित होती दिख रही है। गत वर्ष चीन का व्यापार अधिशेष 676.4 अरब डालर के रिकार्ड स्तर पर रहा। महामारी के बावजूद विदेशी व्यापार में इतनी ऊंची बढ़त ही चीनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती रही, अन्यथा वह पटरी से उतर जाती।

चीनी व्यापार अधिशेष में अमेरिका ही सबसे अहम किरदार है। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 25.1 प्रतिशत बढ़कर 396.6 अरब डालर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन के व्यापार अधिशेष में 60 प्रतिशत का योगदान

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com |

|| Volume 10, Issue 1, January 2021 ||

DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1001094

अकेले अमेरिका का है। वहीं भारत की बात करें तो इस साल चीन के साथ उसका व्यापार घाटा 88 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है। यह पहले ही भारत के रक्षा बजट को पार कर चुका है। वह भी ऐसे समय में जब चीन के साथ पिछले दो वर्षों से सीमा पर तनातनी चल रही है। इसके बावजूद सरकार चीन से जुड़े इस जोखिम को कम करके आंकती दिख रही है। आस्ट्रेलिया और जापान की भी चीन से कारोबारी निकटता है। ऐसे में इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही दिखता है कि क्वाड देश चीन पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय परस्पर व्यापार को वरीयता दें।

बीते दिनों टोक्यो में हुई क्वाड सदस्य देशों की बैठक से पहले अमेरिका ने इस दिशा में एक पहल की है। इसे हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी आइपीईएफ नाम दिया गया है। यह कोई व्यापारिक व्यवस्था न होकर एक आर्थिक मंच है। इसका उद्देश्य भारत सहित 13 सदस्य देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल नियमों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। यह पहल व्यापार बाधाओं या टैरिफ घटाए बिना ही की गई है। दूसरी ओर बाइडन प्रशासन चीन पर लगे व्यापार टैरिफ घटाने की दिशा में विचार कर रहा है, जबकि पहले उसने यही एलान किया था कि जब तक चीन अपना व्यवहार नहीं सुधारेगा, तब तक ये टैरिफ जारी रहेंगे। इस तरह देखा जाए तो बाइडन के नेतृत्व में क्वाड का ध्यान वैश्विक चुनौतियों के मामले में भी बदलता जा रहा है। ये चुनौतियां जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य और लचीली आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी हैं। अपने छोटे दायरे को देखते हुए क्वाड व्यापक अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं दिखता। फिर भी मार्च अपने पहले सम्मेलन में क्वाड देशों ने जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन और अहम एवं उभरती तकनीकों को लेकर कार्यकारी समूह गठित किए। उसी साल सितंबर में जब क्वाड नेता व्हाइट हाउस में मिले तो साइबर सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अंतरिक्ष जैसे विषयों पर तीन और समूह बना दिए। बहरहाल वादे, इरादे और उन्हें पूरा करने के बीच अंतर तो वैक्सीन के मामले में ही दिख गया, जब अमेरिका ने भारत के वैक्सीन निर्माण से लेकर अन्य देशों को उसकी उपलब्धता की राह में अवरोध पैदा कर दिए।

निष्कर्ष

भारत की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी प्रशासन के पूर्व प्रवक्ता द्वारा भारत से ब्रिक्स (Brics) और आरआईसी (RIC) जैसे संगठनों (जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है) के साथ जुड़ाव को प्राथमिकता देने के बजाय "क्वाड में निवेश" करने के लिए कहा। चीन के साथ तनावपूर्ण गतिरोध के बीच, विदेश मंत्री एस. जयजंकर 23 जून को रूस-भारत-चीन (आरआईसी) समूह के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में शामिल हुए थे। ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) समूह के विदेश मंत्रियों ने सीमा गतिरोध के सार्वजनिक होने से कुछ दिन पहले 28 अप्रैल को भी एक बैठक की थी। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई हिस्सों में सेना जुटा ली है, विशेषकर गैल्वान घाटी जो तनाव का केंद्र रहा है।
हालांकि भारत आक्रामक तरीके से चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री राज्यों के साथ संयुक्त विकास समझौते की मांग कर रहा है। जिबूती में एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना और बीजिंग तक कई सुविधाओं के अतिरिक्त पहुंच को रोकने के लिए रणनीति पर विचार किया गया है। 2017 में, नई दिल्ली ने डुक्म (ओमान), असूशन द्वीप (सेशेल्स), चाबहार (ईरान), और सबंग (इंडोनेशिया) सहित विभिन्न स्थानों में समझौता विकसित करने पर तीव्रता दिखाई थी। लेकिन इस संजाल के भीतर अकेले भारतीय नौसेना के संचालन शायद पूरे इंडो-प्रशांत को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाये रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। क्वाड सदस्यों के पास इन बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय परिचालन के पूरक और सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध होने से अवरोध बढ़ सकता है।[6]

क्वाड का टोक्यो सम्मेलन यही दोहराता है कि अत्यंत महत्वाकांक्षी एजेंडा न केवल क्वाड के हिंदू-प्रशांत फोकस को कमजोर करेगा, बल्कि इससे समूह को परिणामोन्मुखी बनाना भी मुश्किल होगा। वैसे भी एक ऐसे दौर में जब अमेरिका यूक्रेन को हथियार आपूर्ति से लेकर तमाम अन्य किस्म की मदद के माध्यम से रूस के साथ छद्म युद्ध में उलझा हुआ है, तब क्वाड के समक्ष नई अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी स्थिति में बाइडन को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन में रूसी अर्थव्यवस्था को सहारा देने की क्षमता है। नि:संदेह सदस्य देशों की निरंतर बैठक और व्यापक सक्रियता से क्वाड मजबूत हो रहा है, लेकिन खतरा यह है कि इससे वह अपनी रणनीतिक दृष्टि और उद्देश्य से भटक सकता है। क्वाड इस समय चौराहे पर खड़ा है। अगर वह कोई ऐसा शोपीस नहीं बनना चाहता है, जो केवल चीनी विस्तारवाद को बढ़ावा देता हो तो उसके सदस्य देशों को एक स्पष्ट रणनीतिक दिशा एवं मायने तलाशने होंगे। इसका पहला चरण तो यही होगा कि क्वाड वैश्विक चुनौतियों के बजाय हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करे।

संदर्भ

1. चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के सदस्यों का कलात्मक ध्वज चित्रण (Publicdomainpictures)
2. चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के सदस्यों का मानचित्रणात्मक विवरण (Wikipedia)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com |

|| Volume 10, Issue 1, January 2021 ||

DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1001094

3. चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के सदस्य राष्ट्रों का ध्वज चित्रण (Prarang)
4. चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के तहत अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर राष्ट्रों के मध्य बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास

5. जेफ एम स्मिथ डेमोक्रेसी के दस्ते: भारत का हृदय परिवर्तन और भविष्य का भविष्य, 13 अगस्त 2020 को युद्ध, चट्टानों पर।
6. तन्वी मदान, आपको चार्ट, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में "क्वाड" के बारे में जानने की जरूरत है, 5 अक्टूबर 2020।

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor:
7.512

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details